



77

न्यायालय माननीय सर्वोच्च राजस्व मण्डल म्वालयर मध्य प्रदेश  
 =====

प्र. क्रं.

निम्न 2568-2/16 नू 2016

बसंता बसोर तनय श्री श्रीटा बसोर

निवासी ग्राम देरी तह. व जिला उत्तरपुर म.प्र. .... आवेदक/निरारानीकर्ता

बनाम

..... गैरनिरारानीकर्ता

शासन मध्य प्रदेश

श्री प्रती राजनी वकिल 18/11/16  
 दया राज 11/8/16  
 प्रस्तुत

निरारानी रा. प्र. क्रं. 19/अ-21/2015-16 पारित  
 आदेश दिनांक 02.07.2016 न्यायालय श्रीमान्  
 अमर कलेक्टर महोदय, उत्तरपुर के द्वारा पारित आदेश  
 के विरुद्ध  
 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 की धारा 50(1) एवं  
 संबोधन अधि. 2011 के तहत ।

R.V.S.  
 4/8/16  
 महोदय,

निरारानीकर्ता आवेदन श्रीमान् के समक्ष निम्नलिखित आशय की  
 निगरानी सादर प्रस्तुत करता है कि :-

1. यह कि भूमि ख. नं. 1699/2 रकबा 0.800 है. सिद्धा मौजा  
 देरी तह. व जिला उत्तरपुर की भूमि का पट्टा रा. प्र. क्रं. 06/अ-198 18/1997-98  
 आदेश दिनांक 30.06.1998 को आवेदक को प्राप्त हुआ था । उक्त भूमि एक  
 पत्तली होने से प्रार्थी को अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो पाती जिससे उसके परिवार  
 का भरण-पोषण करने में असुविधा होती है उक्त भूमि को विक्रय करके आवेदक  
 अन्यत्र उपजाऊ भूमि क्रय करना चाहता है ताकि उसके परिवार का भरण-पोषण  
 हो सके, जिससे वाद भूमि के विक्रय की अनुमति बावत् आवेदन पत्र संहिता की  
 धारा 165(1) 78 ख. के तहत न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, उत्तरपुर के  
 जिरों आगे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जावेगा के समक्ष प्रस्तुत  
 किया । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर र  
 दिया जिससे दुःखित होकर यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

for  
 Q/A

2. :- निगरानी के आधार :-

1. यह कि प्रस्तुत निगरानी आदेश दिनांक 02.07.2016 से निकल लेने में  
 लगे समय की मुजरा करते हुए समय सीमा में श्रीमान् के न्यायालयीन क्षेत्र अधिकार  
 में होने से श्रवण किये जाने योग्य है ।  
 2. यह कि आवेदक गरीब कृषक व्यक्ति है उक्त भूमि एक पत्तली असिंचित

R.V.S.

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 2568-एक/2016 निगरानी

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पदाधिकारी अभिभाषकों के हस्त
5-8-16	<p>यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्र० क्र० 19 अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 2-7-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदक बसंता बसोर पुत्र धरीराज बसोर ने अपर कलेक्टर छतरपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके खाते की ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1699/2 रकबा 0.800 हैक्टर के विक्रय किये जाने हेतु अनुमति माँगी। अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 19 अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 2-7-2016 से विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।</p> <p>3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>4/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने आवेदक की भूमि के खसरा वर्ष 2013-14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 1699/2 रकबा 0.800 हैक्टर भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित है यह भूमि एकफसलीय होने से उपजाऊ है जिसके कारण खेती का समुचित लाभ आवेदक को प्राप्त नहीं होता है इसी कारण से वह इस भूमि को विक्रय करके अन्य कृषि योग्य भूमि की खरीद</p>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

प्र०क० 2568-एक/2016 निगरानी करेगा। अपर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन के तथ्यों की जाँच न कराते हुये विक्रय अनुमति आवेदम निरस्त करने में भूल की है।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत की गई खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 1699/2 रकबा 0.800 हैक्टर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित है तथा खसरा वर्ष 2014-15 के अंकन अनुसार भूमि विक्रय से बर्जित भी नहीं है तथा शासकीय पट्टे की होना मात्र अंकित है। यह पट्टा आवेदक को तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 6 अ 19/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 30-6-1998 से दिया गया है तथा पट्टा आज की स्थिति में 18 वर्ष पुराना है एवं शासकीय अभिलेख में आवेदक भूमिस्वामी दर्ज है। प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही भूमि आवेदक विक्रय कर सकता है ?

1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र० राज्य तथा अन्य एक 2013 रा०नि० 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।
2. भू राजस्व संहिता, 1959(म०प्र०)165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये 10 वर्ष व्यतीत - रिकार्डेड भूमिस्वामी पट्टे के 10 वर्ष उपरांत भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग हेतु स्वतंत्र है।

R  
A

AM

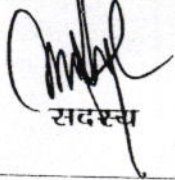
XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 2568-एक/2016 निगरानी

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों
	<p>उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 2-7-16 में इस तथ्य को भी विचार में नहीं लिया है कि आवेदक के वाद विचारित भूमि का 18 वर्ष से भूमिस्वामी चला आ रहा है एवं पट्टा प्राप्ति के उपरांत पट्टे की शर्तों का पालन करने के कारण वह भूमिस्वामी बना है, जिसके कारण आवेदक को विक्रय अनुमति देने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है।</p> <p>6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2 अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 2-7-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 1699/2 रकबा 0.800 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. विक्रय पत्र का पंजीयन वर्तमान वर्ष की प्रचलित शासकीय गाईड लायन के मान से किया जावेगा।</li><li>2. विक्रेता को विक्रय धन प्राप्त होने की सन्तुष्टि के उपरांत उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित करेंगे।</li><li>3. विक्रय पत्र का पंजीयन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर करना होगा। यदि इस अवधि में विक्रय पत्र संपादित नहीं होता है तब यह आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

